

प्रेषक,

कुणाल शर्मा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून दिनांक 06 जून, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या:-548/नियो0/सहभागिता/2013-14 /दिनांक 01 मई, 2013 व शासनादेश संख्या:-1646/XIV-1/2012-5(19)/2010 दिनांक 30-11-2012, नियोजन विभाग द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन सम्बन्धी पत्र संख्या -1148/250 /रा.यो.आ./ मू.अ./2011 दिनांक 30-11-2012, नाबार्ड के परिपत्र संख्या- एनबी. /243/पीसीडी -27/2012 दिनांक 09-10-2012 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्या:-284/XXVII (1)/ 2013 दिनांक 30-03-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/ कृषेत्तर ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी0पी0एल0 परिवारों, सामान्य कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण/दीर्घकालीन ऋण/आवास ऋणों पर तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कम्प्यूटर ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित ₹1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करने के लिये श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दावों का निबन्धक स्तर से सम्यक् परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। वर्ष में स्वीकृत ऋणों पर लागू दरों के सापेक्ष दिनांक 31.03.2015 तक ही सस्ते ऋण के सापेक्ष वार्षिक देयता के अनुरूप ब्याज अनुदान अनुमन्य होगा।

(2) राज्य सरकार के स्तर से देय ब्याज अनुदान की गणना भारत सरकार तथा नाबार्ड के स्तर से सस्ते ऋणों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का समायोजन करते हुये की जायेगी तथा उसी के अनुरूप संबंधित बैंको को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त मांग प्रस्तुत करने तथा भुगतान किये जाने की स्थिति में बैंको तथा विभाग के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-284/XXVII (1)/ 2013 दिनांक 30-03-2013 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। योजना का नियोजन विभाग से कराये गए मूल्यांकन अध्ययन की संस्तुतियों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

*Due*



(4) धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह बी0एम0-13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425- सहकारिता आयोजनागत- 00 -800-अन्य व्यय-03-सहकारी सहभागिता योजना- 00-50-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-17P/XXVII-(4)/2013, दिनांक 23 मई, 2013 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( कुणाल शर्मा )  
सचिव।

संख्या:- 789 (1)/XIV-1/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
9. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
10. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( यू0सी0कबडवाल )  
अपर सचिव।